

सम्पादकीय

लोकल-ग्लोबल साधती भारत शिक्षा नीति : कतिपय सतर्कता बिन्दु

NEP2020 Balancing Local and Global : Few Points of Caution

भारत स्वतंत्र हुआ। औपनिवेशिकता के खुमार को कम करने के लिए अपनी देशज शिक्षा नीति बनाने के प्रारम्भिक प्रयास में प्रमुख हैं :

पहला, राधाकृष्णन उच्चशिक्षा कमीशन (1948) जिसमें ज्ञान-विज्ञान, राजनीति, उद्योग, आदि क्षेत्रों में नेतृत्व और कौशल विकास पर बल दिया गया। सिफारिश में उच्च शिक्षा में नैतिक मूल्यों का संवर्धन, कुछ मिनट का ध्यान, भारतीय भाषा माध्यम, धर्म का दार्शनिक अध्ययन, आदि शामिल थे।

दूसरा, शिक्षा पर राष्ट्र नीति (National Policy on Education) : NPE 1968 में और इसका परिष्कार 1992 में, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में एकरूपता, हिन्दी-अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा को अपनाना, संस्कृत भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देना और शिक्षा पर GDP का 6% व्यय करना इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं।

तीसरा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowledge Commission): 2007 में 21वीं सदी की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा तंत्र को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में विज्ञान-प्रौद्योगिकी संस्थानों में ज्ञान-सृजन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए गए। 27 विषय क्षेत्रों को इंगित किया गया जैसे भाषा, अनुवाद, ग्रंथालय, ज्ञान-नेट, स्कूली शिक्षा, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, रिसर्च, उद्यमिता आदि। इसमें तात्कालिक वैश्विक प्रतिद्वंद्विता पर जोर था। स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी पर बल दिया गया। कक्षा 1 से अंग्रेजी की शिक्षा दिए जाने की वकालत की गई।

राधाकृष्णन कमीशन (1948) की सिफारिशें भारतीय संस्कृति प्रधान थी, लेकिन इसमें केवल उच्च शिक्षा की बात की गई थी, NPE (1968/92) की सिफारिशें कार्यान्वयन में सुगमतापरक थीं जबकि 2007 की NKC (राष्ट्रीय ज्ञान आयोग) सिफारिशें औद्योगिक दृष्टि से मानव संसाधन तैयार करने की थीं।

चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 2020 नई सोच से प्रेरित है। भारतीय संस्कृति से सम्पन्न उद्यमशील प्रतिभा विकास और उत्कृष्ट नवाचार परक है। NEP 2020 में चार अध्याय हैं – स्कूली शिक्षा (48 पृष्ठ), उच्चतर शिक्षा (48 पृष्ठ), अन्य विचारणीय मुद्दे (15 पृष्ठ), और क्रियान्वयन रणनीति (15 पृष्ठ)।

पहले अध्याय में वर्णित स्कूल शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान रखा गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास हो जाता है। इसलिए 3 से 6 तक आयुवर्ग के लिए बाल शिक्षा में पोषण, स्वास्थ्य और आचरण पर बल दिया गया तथा आयु 7 से 8 को कक्षा 1 व 2 के समान रखा गया। आयु 3 से 8 काल को व्यक्ति और राष्ट्र की ज्ञान-क्षमता एवं संस्कार की नींव की भांति देखा जाए, यह माना गया। प्राथमिक शिक्षा 5 वर्षों की जगह 8 वर्षों की जगह प्रस्तावित है – बुनियादी शिक्षा 3-8 आयु में और तैयारी शिक्षा काल 9-11 आयु में विभाजित किया गया। शेष वर्गीकरण पूर्ववत् रहा। इस प्रकार स्कूली शिक्षा 5+3+3+4 चरणों में रखी गई है।

बुनियादी शिक्षा की सफलता राज्य सरकारों पर निर्भर है। समग्र अधिगम और एक पुस्तक की नीति के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाया जाए। शक्यता (Can do) और संकल्प (Will do) का भाव दृढ़ हो। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ नवोन्वेषी अनुसंधानपरक प्रवृत्ति का विकास हो। कक्षा 6-12

तक कौशल विकास पर बल दिया जाए। संस्कृत में विज्ञान और भाषा की वैज्ञानिकता को भी बताया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कोडिंग को शामिल करना अच्छा है, लेकिन इसे भारतीय भाषा में भी समझाया और अभ्यास कराया जाए, कुंजियों पर नागरी वर्ण उकैरे हुए फ्लैक्च कीबोर्ड अनिवार्यतः दिए जाएं।

उद्योग कार्यबल (19–24 वर्ष के युवा) वोकेशन शिक्षा के माध्यम से भारत में 5%, और दक्षिण कोरिया में 96% है। विडम्बना है कि पिछले चार दशक के प्रयासों के बावजूद भारतीय समाज में वोकेशनल शिक्षा को दायम दर्जे का मानते हैं, प्रतिष्ठित नहीं बन सकी। सुझाव है कि एक, एकेडेमिक शिक्षा में कौशल विकास पर करीब 40% बल दिया जाए। दो, वोकेशन सर्टिफिकेट को एकेडेमिक सर्टिफिकेट के समतुल्य माना जाए जिससे उच्चशिक्षा में प्रवेश आसान हो। तीन, क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था हो। किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेनिंग को मान्यता दी जाए।

दूसरे अध्याय में उच्च शिक्षा के सम्बंध में सिफारिशें हैं। UG व PG स्तर की शिक्षा में भारतीय संस्कृति परिचय, विविध विषयों का समुचित समावेश, विशेषज्ञता, कौशल-क्षमता, सहकारिता, नैतिकता और नवोन्वेषी अनुसंधान परक प्रवृत्ति के विकास पर बल दिया जाए। सभी प्रतिभावान प्रतिभागियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुलभ हो। प्रवेश और प्रोग्राम छोड़ने का लचीला प्रावधान हो। अन्य संस्थान से कोर्स करने पर क्रेडिट मान्य हों।

उच्च शिक्षा में GER प्रवेश अनुपात 26.3% (2018) से 50% (2035) बढ़ाने का लक्ष्य है। कोरोना काल में ऑन-लाइन क्लास की सहज स्वीकृति हो गई। लेकिन ऑन-लाइन और इन क्लास मिश्रित शिक्षण विधा (Blended hearing) प्रभावी होगी। UG स्तर पर बीच में भी छोड़ने और बाद में फिर आगे पढ़ाई करने का भी प्रावधान किया है। 1 वर्ष के बाद छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष बाद डिप्लोमा, 3 वर्ष बाद एडवांस्ड डिप्लोमा ही, डिग्री 4 वर्ष बाद ही दी जाए। 3 वर्ष के बाद डिग्री दिए जाने की सिफारिश उचित नहीं है।

Washington Accord के अनुसार 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम मान्य है। NBA से accreditation भी 4 वर्ष के डिग्री प्रोग्राम को मिल सकेगा। हरेक विश्वविद्यालय/संस्थान को समग्र पाठ्यक्रम (holistic curriculum) बनाने, जरूरी संसाधन (Resources) जुटाने और लक्षित परिणाम (Outcome) के बारे में स्पष्ट योजना बनाने की आवश्यकता है।

समग्र पाठ्यक्रम (holistic curriculum) में अन्य विषयों को उपयोगिता के आधार पर जोड़ा जाए। NEP 2020 में डिग्री प्रोग्राम से अपेक्षाएं अधिक हैं, किसी एक विषय में गहराई और अन्य रुचिकर विषयों का सतही ज्ञान हो। हिन्दी/भारतीय भाषा को युक्तिपूर्ण तरीके से उच्चतर शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। *संक्रमण काल में मिश्रित विधा को अपनाएं जिसमें बोलचाल की भाषा में बात समझायें, लेकिन प्रचलित तकनीकी शब्द अंग्रेजी के भी रहें। यदि किसी तकनीकी शब्द का हिन्दी समतुल्य शब्द है तो उसका प्रयोग भी साथ-साथ करें।* हिन्दी शब्द सामाजिक संवेदना का भाव देता है, तो अंग्रेजी का प्रचलित तकनीकी शब्द वैश्विक (global) प्रतिद्वंद्विता के प्रति तैयारी का प्रतीक है। परिवेश (local) से जुड़े रहें और वैश्विक (global) प्रतिद्वंद्विता भी बनें। इससे इंडस्ट्री में जॉब पाने में भी परेशानी नहीं होगी।

हिन्दी/भारतीय भाषा माध्यम में तकनीकी शिक्षा के लिए क्या हम तैयार हैं ?

अभी नहीं, आज तकनीकी शब्दावली वेब पर खोजी नहीं जा सकती, सर्चबल नहीं है। उच्चशिक्षा में भारतीय भाषा में शब्द निर्माण एवं निर्वचन और तकनीकी अनुवाद विषयों को पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए

वैज्ञानिक नए शब्द सृजन में असहाय रहते हैं। तकनीकी पुस्तकें हिन्दी/भारतीय भाषा में लाने के लिए प्रस्तावित एक अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान (ITI) बनाने से ही काम नहीं चलेगा।

सुझाव है कि तकनीकी संस्थानों के समूह बनें और विषयवार अनुसृजन कार्य किया जाए। पढ़ाने के बाद शब्दावली प्रणयन गुणवत्ता पूर्ण होगा। तकनीकी शिक्षा में शिक्षण-विधाओं (Pedagogy) एवं अनुसृजन से परिचित कराने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रावधान हो। यह 2-3 माह का कोर्स हो सकता है। ग्रीष्म काल के अवकाश में ऐसा कोर्स चला सकते हैं। NITTR में इस प्रकार के कोर्स की व्यवस्था हो।

तकनीकी और मेडीकल शिक्षा में हिन्दी/भारतीय भाषा का प्रयोग सामाजिक अपेक्षा है, जिससे प्रशिक्षित विशेषज्ञ अपने परिवेश और देश की समस्या को उत्कृष्टता के साथ हल कर सकें। लौकिक परिवेश में पारस्परिक विचार विनिमय में आसानी हो, और इसके साथ वैश्विक स्तर पर भी प्रतिद्वंदी बनें। इसलिए आवश्यक है कि उन्हें हिन्दी/भारतीय भाषा और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान हो, दोनों में काम करने, और समझने समझाने की क्षमता हो।

चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम निर्माण एवं कार्यान्वयन :

पाठ्यक्रम (Curriculum) NEP2020 के अनुरूप समग्र (Holistic) हो, सुचारु चलाने के लिए समुचित संसाधन (Resources) हों। शिक्षण संस्थान का लक्ष्य रहेगा कि संस्थान की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो। संस्थान की प्रतिष्ठा का मापदण्ड है छात्रों को अच्छी नियुक्तियाँ मिलें, अधिकतम प्लेसमेंट हो, शिक्षकों को रिसर्च और प्रमोशन के अवसर मिलें, और शिक्षण संस्थान को उच्च, गुणवत्तापूर्ण संस्थान के रूप में पहचान मिले। तभी अधिक से अधिक मेधावी छात्र एडमिशन लेंगे।

शिक्षकों को सम्मान प्रमोशन की बात इस लिए कहनी पड़ रही है कि एकेडेमिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स (API :Academic Performance Index) की गणना करते समय शिक्षण के द्वारा हिन्दी/भारतीय भाषा में पढ़ाने, नोट्स बनाने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखाने और रिसर्च पेपर लिखने को हेय न समझा जाए, प्रत्युत इसे वांछनीय मानकर 20 प्रतिशत रिसर्च पेपर हिन्दी/भारतीय भाषा में आवश्यक किए जाएं। *NAAC, NBA और NIRF में मूल्यांकन पैरामीटर में बदल करना अनिवार्य है, अन्यथा शिक्षा नीति का सफल कार्यान्वयन सम्भव नहीं है।*

पाठ्यक्रम तैयार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि डिग्री की समयावधि 4 वर्ष में संस्कृत भाषा परिचय, भारतीय संस्कृति, भारत ज्ञान परम्परा, तकनीकी अनुसृजन के सिद्धान्त जैसे नए विषय जुड़ेंगे। CBCS (चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) के अन्तर्गत कोर विषय से परे मेडीकल, म्यूजिक, भाषा, प्रबंधन आदि किसी विषय का अध्ययन भी चुन सकते हैं। थ्योरी के साथ स्वयं कर सकने के कौशल का भी विकास हो। इन्नोवशन/रिसर्च आधारित प्रोजेक्ट भी करे। विद्यार्थी से अपेक्षाएं बहुत, लेकिन समय कम है। पाठ्यक्रम बनने के बाद सुबोध पाठ्य-सामग्री बनाना भी आवश्यक है। कई विषय, कई पुस्तकें, कई NPTEL / SWAYAM पर लेक्चर हैं, कई प्रोफेसर नई पुस्तकें लिखना चाहते हैं। भाषान्तर के लिए सर्चबल तकनीकी शब्दावली हो, पारिभाषिक शब्दावली हो, शब्द निर्माण की सहायक सामग्री संस्कृत-हिन्दी, संस्कृत-इंग्लिश, हिन्दी समानान्तर, अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश मिलें। हिन्दी/भारतीय भाषा में सुबोध पाठ्यक्रम सामग्री तेजी से तैयार कराने के लिए शिक्षक लेखकों को समेकित अनुसृजन सिस्टम (ITS : Integrated Transcreation System) उपलब्ध कराए जाएं। MEITY (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के माध्यम से ITS को उपलब्ध कराया जा सकता है। AICTE से भी प्रोत्साहन संभव है।

समेकित अनुसृजन सिस्टम (Integrated Transcreation System) में मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम, OCR, हस्तलेख पहचान तंत्र, स्पीच टू टैक्स्ट (S2T), टेक्स्ट टू स्पीच (T2S), ट्रांसलेशन मोमोरी, सर्चबल तकनीकी शब्दावली, संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी के शब्दकोश, समान्तर कोर्पोरा, संक्षेपक (Summarizer), उत्तम लेखों को संग्रह करने की सुविधा, Chrome, Firefox, MS Edge आदि ब्राउजर पर 10 सुंदर यूनीकोड फॉन्ट, नागरी वर्ण उक्रेरे हुए INSCRIPT इंस्क्रिप्ट मानक कीबोर्ड, आदि का समावेश हो। समेकित अनुसृजन सिस्टम से सुबोध पाठ्यसामग्री तैयार करने की गति चार पांच गुनी बढ़ जाएगी। मौलिक लेखन की प्रवृत्ति में भी संवर्धन होगा।

शोध संवर्धन : भारत का ग्लोबल इन्नोवेशन इंडेक्स 2015 में 81 था, 2019 में 52 हो गया, और 2020 में 48. इन्नोवेशन में प्रति वर्ष सुधार हो रहा है। रिसर्च के सम्बंध में दो बातें हैं— Quality (गुणवत्ता) और Relevance (सार्थकता/उपादेयता)। भारत में रिसर्च गुणवत्तापूर्ण जर्नल में प्रकाशित किए जाने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे उसके Citation यानि दूसरों के द्वारा उसे खोलने-पढ़ने की संख्या बढ़े और एकेडेमिक परफोर्मेंस इंडेक्स (API) की गणना में लाभ मिले, प्रमोशन मिले। कई विभाग और मन्त्रालय भी शोध विकास के लिए वित्तीय सहायता देते हैं। इनके प्रोजेक्ट का लाभ प्रायः सामान्य जन तक नहीं पहुंचता। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ढाक के तीन पात। *सुझाव है कि सभी शोध विकास परियोजनाओं का रिसर्च ऑडिट अनिवार्य हो।*

प्रस्तावित NRF (नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन) से अधिक से अधिक युवा वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए ग्रांट की व्यवस्था हो। आत्मनिर्भर भारत के सम्बंध में रिसर्च देश की समस्याओं को हल करने में सहायक हो, उपयोगी हो। NRF बेसिक रिसर्च पर फोकस करे, जो भविष्योन्मुखी हो, समावेशी हो, वैश्विक प्रतिद्वंदी हो और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम बने। इसके लिए खुलापन (openness), पारदर्शिता (Transperancy) और सहभागिता (collaboration) आवश्यक हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रिसर्च लैब खोली जाएं, जहाँ जिज्ञासामूलक शोध (curiosity driven research) और औद्योगिक शोध-विकास पर मिलकर काम हो।

NEP 2020 में बहु विषयक विश्वविद्यालय (Multi-disciplinary University) बनाने और समग्र शिक्षा (Holistic Education) की सिफारिश की गई है। लेकिन यह लचीले ढंग से अन्य विशेषज्ञता संस्थानों के सहकार सहयोग से सम्भव है। 80-20 के अनुपात में अध्यापन प्रधान (Teaching Predominant) और रिसर्च केन्द्रित (Research Focused) स्वायत्त शिक्षण संस्थाएं चिह्नित की जाएं। इसी स्वीकृति के आधार पर इन संस्थानों को उत्कृष्ट बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्येक रिसर्च केन्द्रित संस्थान 5-7 अध्यापन प्रधान कॉलेजों को मेंटर करने की जिम्मेदारी ले। शिक्षण कौशल उत्कर्षण, छात्रों को रिसर्च लैब की सुविधा, पाठ्यक्रम, अध्यापन, नवाचारमय प्रयोगात्मक कौशल विकास आदि में सुधारात्मक सहयोग दें। उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में संस्कृत का वैज्ञानिक परिचय और संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान के विषय शामिल किए जाएं। तकनीकी संस्थानों में तकनीकी अनुसृजन कोर्स भी दिया जाए जिससे वे आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साहित्य का हिन्दी/भारतीय भाषा में अनुवाद, अनुसृजन एवं मौलिक लेखन में समर्थ हों। विशेषज्ञ समिति के द्वारा डिजिटल शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए।

. . . ओम विकास

dr.omvikas@gmail.com